बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 185 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 08 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

झाड़-फूंक की आड़ में शर्मनाक करतूत, आरोपी मौलवी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली। आस्था और अंधविश्वास की आड़ में किए गए एक बेहद शर्मनाक अपराध में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मौलवी को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह मामला एक मासूम लड़की की कमजोर शारीरिक और मानसिक स्थिति के अलावा उसके परिवार के अंधविश्वास का फायदा उठाकर किए गए शोषण का है. जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा की बेंच ने कहा कि आरोपी ने परिवार के भरोसे और लड़की की नाजुक हालत का गलत इस्तेमाल किया. ऐसे गंभीर आरोपों में राहत देना उचित नहीं है. खासकर जब ट्रायल अंतिम चरण में पहुंच चुका है. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक, पीड़िता लंबे समय से बीमार थी.

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, जयराम रमेश बोले- पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि भारत की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग नहीं पड़ा, जैसा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद हुआ था। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इसके उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसीम मुनीर का गर्मजोशी से स्वागत किया है।

ट्रंप ने किया था युद्धविराम का दावा

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने वाले युद्धविराम की पहली घोषणा 10 मई 2025 को शाम 5:37 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की थी। उन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप से यह संभव हुआ। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने बाद में भी कई बार इस दावे को दोहराया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इसका खंडन नहीं किया।

अनिल चौहान के बयानों का दिया हवाला

कांग्रेस नेता ने कहा कि 30 मई 2025 को सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने माना था कि भारत को शुरुआती चरण में सामरिक गलतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बाद में रणनीति में सुधार कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर सटीक हमले किए। जयराम रमेश ने यह भी कहा

कि 10 जून 2025 को जकार्ता में भारतीय दूतावास के रक्षा अटैची ने स्वीकार किया था कि 7 मई 2025 को राजनीतिक नेतृत्व की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत को कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े। उन्होंने दावा किया कि 4 जुलाई 2025 को उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से गहरी मदद मिली। इसमें हथियारों और गोला-बारूद के अलावा सैटेलाइट इमेजरी और रियल-टाइम टारगेटिंग सपोर्ट भी शामिल था।

मोदी सरकार का चीन के प्रति नरम रुख

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद मोदी सरकार का चीन के प्रति नरम रुख जारी है। पार्टी ने लद्दाख में पारंपरिक गश्त अधिकारों के नुकसान, चीन से रिकॉर्ड आयात और एफडीआई नियमों में ढील जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया।

अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर क्या बोले?

जयराम रमेश ने कहा कि 1999 के कारगिल युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा समिति बनाई थी, जिसने घटनाक्रम की जांच कर भविष्य के लिए सुझाव दिए थे। कांग्रेस ने संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इसी तरह की समीक्षा की जरूरत है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे, की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था, लेकिन 10 मई को सैन्य अधिकारियों के बीच हॉटलाइन वार्ता के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी थी।

ऑपरेशन सिंदूर - जंग में पाकिस्तान को कैसे धोया, कितना हुआ था नुकसान; एयर मार्शल ने बताई 23 मिनट की कहानी

नई दिल्ली। आज भारत ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ बना रहा है। इस मौके पर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की उस प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया, जब उसकी शांति की प्रतिबद्धता को कमजोरी और संयम को निष्क्रियता समझा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, एयर मार्शल भारती ने कहा कि भारत ने हमेशा जियो और जीने दो के दर्शन का पालन किया है। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि जब भी इस भावना का उल्लंघन होता है, तो राष्ट्र निर्णायक और समझौताहीन कार्रवाई के साथ जवाब देता है। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। उन्होंने आगे बताया हमने 7 मई को उनके 9 आतंकवादी कैंपों पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका सबूत सबके सामने है। हमने उनके 11 हवाई अड्डों पर हमला किया। हमने उनके 13 विमानों को

नष्ट कर दिया, चाहे वे ज़मीन पर हों या हवा में। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हमे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। न तो कोई सैन्य ढांचा और न ही यादातर नागरिक ढांचे... वे चाहे कुछ भी कहें, याद रखें कि किस्से-कहानियां और बयानबाजी आपको जीत नहीं दिलाते। जीत का पैमाना तो ठोस तथ्य होते हैं...इसी प्रेस वार्ता में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान ने 100 से यादा सैनिक खो दिए। उन नौ आतंकवादी कैंपों में 100 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा, उनकी सम्मान और पुरस्कारों की सूची, जो इंटरनेट पर जारी हुई थी, उससे हमें पता चला कि उनमें से कई पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए थे। नियंत्रण रेखा पर हुई झड़पों में उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ा, उसमें उन्होंने 100 से ज्यादा सैनिक खो दिए। आखिरकार, अगर पाकिस्तानी अपनी युद्ध लड़ने की क्षमता में उतना ही निवेश करते, जितना वे अपनी कहानी गढ़ने में करते हैं, तो मुझे लगता है कि वे कहीं यादा बेहतर प्रदर्शन करते। इसी प्रेस वार्ता में अपनी बात रखते हुए वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीतिक सोच को रेखांकित किया, जिसने एक सटीक और स्पष्ट जनादेश तथा आवश्यक ऑपरेशनल स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्णायक सैन्य कार्रवाई करना संभव हो सका। 6-7 मई की रात को, नौसेना के जवानों ने भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों में भी हिस्सा लिया, जिससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकजुटता प्रदर्शित हुई। जैसे-जैसे यह अभियान आगे बढ़ा, भारतीय नौसेना की अग्रिम तैनाती ने पाकिस्तानी नौसेना और वायु सेना की इकाइयों को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने पर मजबूर कर दिया, वे काफी हद तक अपने बंदरगाहों तक ही सीमित रह गए या अपनी तटरेखा के करीब ही संचालित होते रहे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की उस क्षमता को साबित किया, जिसके तहत वह किसी भी असममित उकसावे का जवाब सोच-समझकर, सटीक और संतुलित बल के साथ दे सकता है।

दिल्ली में रेत के ढेर से उठी बदबू तो खुला मजदूर की मौत का राज, हत्या के बाद निर्माणाधीन इमारत में छिपाई थी लाश

पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले के नवीन शाहदरा इलाके में निर्माणाधीन इमारत की छत पर रेत के नीचे दबा युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। घटना जे-4 नवीन शाहदरा की है। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, निर्माण स्थल से बदबू आने पर श्रमिकों ने सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चौथी मंजिल की छत पर जांच की तो युवक का शव रेत-बदरपुर के नीचे दबा मिला। शव काफी सड़ चुका था, जिससे अंदेशा है कि हत्या तीन से चार दिन पहले की गई थी। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि मृतक श्रमिक था, लेकिन वह इस निर्माणाधीन इमारत में काम नहीं कर रहा था। संभावना है कि उसे किसी अन्य जगह से यहां बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को छिपाने के लिए रेत के नीचे दबा दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के तरीके और अन्य तथ्यों का पता चल सकेगा। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और निर्माण स्थल से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है।

पंजाब ब्लास्ट पर संजय सिंह का बयान- बीजेपीपर नफरत फैलाने का आरोप, कहा- भाजपाइयों तुम्हारा इतिहास आईएसआई के साथ

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और राय्सभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने पंजाब में हुए दो विस्फोटों को लेकर भाजपा की बयानबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए मोड़ विस्फोट की याद दिलाता है। संजय सिंह ने कहा कि तब भी अकाली दल और भाजपा की सरकार थी। उस मोड़ विस्फोट का भी कोई पता नहीं चला था। अब बंगाल चुनाव के तुरंत बाद भाजपा मिशन पंजाब की बात कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि यह वहां के अमन-चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना और झगड़े कराना है। उन्होंने भाजपा पर आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाया। सिंह ने पुलवामा विस्फोट में 350 किलो आरडीएक्स के स्रोत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह अभी तक पता नहीं चला है कि आरडीएक्स देश में कैसे आई। संजय सिंह ने पहलगाम घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए। इस पर ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। लेकिन सुरक्षा किसके आदेश पर हटाई गई, इसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है। सिंह ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है।

मणिपुर और बंगाल में हिंसा

संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर बीते तीन वर्षों से जल रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भाजपा को इसकी कोई चिंता नहीं है। वे देश का माहौल खराब और बिगड़ा हुआ चाहते हैं। उन्होंने बंगाल में चुनाव जीतने के बाद हुई हिंसा का भी उल्लेख किया। बीते दिन मुख्यमंत्री के दावेदार सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या हुई। इससे पहले तृणमूल के लोगों पर हमले हुए और उनके कार्यालय जलाए गए।

पीएम मोदी पर लगाए आरोप

संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव की राजनीति की बात करते हैं। लेकिन भाजपा पंजाब में भी यही सब करना चाहती है। उन्होंने देश और पंजाब के लोगों को ऐसी घृणा फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहने की सलाह दी। सिंह ने याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का एक सदस्य लश्कर-ए-तैबा से जुड़ा था। मध्य प्रदेश में भी उनके कुछ कार्यकर्ता आईएसआई से जुड़े पाए गए थे। उन्होंने भाजपा की बेचैनी को उनकी चालबाजियां बताया।

दिल्ली के 310 परिवारों को सरकारी अल्टीमेटम, 15 दिन में खाली करने होंगे घर; काशी की तर्ज पर संवरेंगे यमुना घाट

नई दिल्ली। काशी के गंगा घाटों की तर्ज पर दिल्ली में भी यमुना किनारे स्थित पक्के घाट दिव्य, भव्य व आस्था से परिपूर्ण होंगे। दिल्ली सरकार ने उस दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। उसके तहत यमुना बाजार स्थित पक्के 30 घाटों के किनारे के पंडों (तीर्थ पुरोहित) की बसावट को हटाने के आदेश दिए हैं। उससे संबंधित नोटिस जिला प्रशासन ने मंगलवार को जारी किया है, जिसमें, 15 दिन की अवधि दी गई है। हालांकि, इस प्रयास के साथ दशकों से कई छह से सात पीढ़ियों से रहते पंडा परिवारों की चिंता बढ़ गई है। वे यमुना से जुड़ाव, आजीविका, कर्मकांड व धार्मिक आस्था का हवाला देकर घाट से 300 मीटर के दायरे में उन्हें रहने के लिए जगह तथा कर्मकांड के लिए घाटों पर उचित स्थान देने की मांग की है। ये पक्के घाट पांडव कालीन माने जाते है। प्रमाणिक उल्लेख 100 वर्ष से कुछ अधिक का है। उन्हें पुरानी दिल्ली के धनाढ्य व धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों द्वारा तकरीबन 100 वर्ष पूर्व बनवाए गए हैं। जबकि, घाट ऊपर पंडों के पुराने मकान है, जो एक चौड़ी मोटी दीवार तक विस्तार लिए हुए है। कई घाटों की पंडे महिलाएं हैं। पंडा सुरेश चंद शर्मा कहते हैं कि उन्हें घाटों के पुनर्विकास से आपत्ति नहीं है। पर उसमें हाई कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए और घाट के नजदीक ही पुर्नवास होना चाहिए। यहां पंडों का करीब 60 परिवार रहता है। जिनके 310 घरों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने डीडीए कानून के तहत खाली करने का नोटिस भेजा है। पंडे उर्मिला शर्मा बताती हैं कि वर्ष 2006 में भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने घाट खाली कराने की कोशिश की थी। तब कुछ लोग मान गए और बवाना में आवंटित जमीन ले ली थी। लेकिन अधिकांश पंडों ने यमुना छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मामला हाई कोर्ट में गया, तब कोर्ट ने उन लोगों को घाट के 300 मीटर के दायरे में रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराने का आदेश डीडीए को दिया था, 20 वर्ष बाद भी उस निर्णय का पालन नहीं हुआ है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना पर अगाध श्रद्धा व्यक्त की है। जीत के बाद उन्होंने यमुना आरती कर पदभार ग्रहण किया। पूर्व राय्पाल वीके सक्सेना का भी यमुना की सफाई व सुंदरता पर पूरा जोर रहा। कश्मीरी गेट स्थित कुदेशिया घाट को नया व भव्य रूप देकर वासुदेव घाट बनाया गया है। उसी तरह की कोशिश यमुना बाजार के 30 घाटों को लेकर भी है। बसावट खाली कर वहां हरियाली, भक्तों के लिए सुविधा और स्वच्छ वातावरण विकसित करने पर है।

बंगाल का जनादेश और विपक्ष की जिद का गणित

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का जनादेश केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, यह विपक्षी राजनीति की रणनीतिक भूलों का भी दस्तावेज है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को यदि केवल संगठन, संसाधन और प्रचार की शक्ति से समझा जाए तो यह अधूरा विश्लेषण होगा। बंगाल का वास्तविक चुनावी गणित बताता है कि भाजपा जितनी अपनी ताकत से जीती, उससे कम नहीं विपक्ष की बिखरी हुई राजनीति के कारण भी सत्ता तक पहुंची। इस चुनाव ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में केवल जनाधार ही नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यावहारिकता भी निर्णायक होती है। चुनाव परिणामों पर दृष्टि डालें तो भाजपा को लगभग 45.8 प्रतिशत मत प्राप्त हुए और वह 207 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत तक पहुंच गई। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को लगभग 40.8 प्रतिशत मत मिले, लेकिन वह केवल 80 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने 284 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और लगभग 43.5 लाख वोट प्राप्त किए, किंतु उसके हिस्से में केवल 2 सीटें आईं। यही वह बिंदु है जहां बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। कांग्रेस चुनाव में निर्णायक शक्ति नहीं बन सकी, लेकिन उसके वोट निर्णायक प्रभाव अवश्य छोड़ गए। राजनीतिक गणित का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तृणमूल कांग्रेस जिन सीटों पर हारी, उन सभी सीटों पर हार का कुल अंतर लगभग 24.8 लाख वोट रहा। इसके मुकाबले कांग्रेस को अकेले लगभग 43.5 लाख वोट मिले। अर्थात कांग्रेस का कुल मत-आधार तृणमूल की कुल हार-मार्जिन से लगभग 1.75 गुना अधिक था। यह आंकड़ा केवल सांख्यिकीय तुलना नहीं, बल्कि चुनावी संदेश है। इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस के सभी वोट तृणमूल को स्वतः स्थानांतरित हो जाते, किंतु यह अवश्य स्पष्ट करता है कि विपक्षी मतों का विभाजन भाजपा के लिए सबसे बड़ा लाभकारी कारक सिद्ध हुआ। यही वह बिंदु है जहां ममता बनर्जी की राजनीतिक रणनीति पर सबसे गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने यह चुनाव वस्तुतः भाजपा के विरुद्ध नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के विरुद्ध लड़ा। यह रणनीति राजनीतिक आत्मविश्वास से अधिक राजनीतिक जिद साबित हुई। बंगाल की राजनीति में कांग्रेस भले कमजोर हो चुकी हो, लेकिन वह मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे क्षेत्रों में अब भी प्रभावी सामाजिक आधार रखती है। यदि तृणमूल कांग्रेस ने व्यावहारिकता दिखाते हुए सीमित सीट-समझौता किया होता, तो भाजपा के लिए इतनी सहज जीत संभव नहीं थी। यही चुनावी अंकगणित बताता है कि यदि तृणमूल और कांग्रेस के बीच पूर्व-निर्धारित तालमेल होता, तो बंगाल में मुकाबला एकतरफा नहीं, बल्कि सीधा और कांटे का हो सकता था। तृणमूल के लगभग 4.08 करोड़ और कांग्रेस के लगभग 43.5 लाख वोट मिलकर भाजपा के कुल मतों के लगभग बराबर पहुंचते। ऐसी स्थिति में भाजपा की 207 सीटों की बढ़त संभवतः 125 से 150 सीटों के बीच सिमट सकती थी। तृणमूल 80 पर नहीं रुकती और कांग्रेस 2 पर नहीं सिमटती। बंगाल में या तो त्रिशंकु विधानसभा बनती या बहुत कमजोर बहुमत की सरकार। यह चुनाव कांग्रेस की शक्ति से अधिक तृणमूल की रणनीतिक विफलता का चुनाव था। कांग्रेस ने भले केवल दो सीटें जीती हों, लेकिन उसके वोटों ने यह साबित कर दिया कि बंगाल में विपक्षी राजनीति का स्थान अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया कि जनाधार होते हुए भी राजनीतिक अकेलापन घातक हो सकता है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पराजय भाजपा से नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक जिद से हुई। लोकतंत्र में जनादेश केवल जनता नहीं देती, उसे राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों से आकार भी देते हैं। बंगाल का जनादेश यही कहता है कि भाजपा की विजय जितनी उसकी राजनीतिक सफलता है, उतनी ही विपक्ष की असफल एकजुटता की भी कहानी है। यह परिणाम केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि विपक्ष को यह चेतावनी देने का जनादेश है कि यदि अहंकार, क्षेत्रीय वर्चस्व और नेतृत्व की जिद, राजनीतिक यथार्थ पर भारी पड़ेगी, तो जनादेश विरोधियों को नहीं, प्रतिद्वंद्वियों को लाभ पहुंचाएगा। बंगाल का संदेश स्पष्ट है-भाजपा जीती जरूर, लेकिन विपक्ष हारा उससे पहले था।

बच्चों को जीवन के लिए तैयार करती है 'मोरल साइंस'

आज की तेजी से बदलती दुनिया में, शिक्षा को अक्सर अंकों, रैंकिंग और प्रतिस्पर्धी सफलता से मापा जाता है। स्कूल गणित, विज्ञान और तकनीक जैसे विषयों पर भारी ध्यान केंद्रित करते है, जो निस्संदेह महत्वपूर्ण है। हालांकि, कई कक्षाओं से धीरे-धीरे कुछ अनिवार्य चीज ओझल हो गई है-मूल्य। पुराने समय में, स्कूलों में 'मोरल साइंस' (नैतिक विज्ञान) नामक एक विषय होता था और सुबह की सभाएं अक्सर राष्ट्रगान और एक सरल भजन के साथ शुरू होती थीं। ये केवल अनुष्ठान नहीं थे, इन्होंने युवा दिमागों को आकार देने में एक शांत लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभाई। आज की जटिल, डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे बच्चों के लिए इन प्रथाओं को वापस स्कूलों में लाना गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मोरल साइंस कभी भी परीक्षा या ग्रेड के बारे में नहीं थी। यह एक अच्छा इंसान बनने के बारे में थी। सरल कहानियों, चर्चाओं और उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को ईमानदारी, दया, सम्मान, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ देने और साझा करने की कला सिखाई जाती थी। ये सबक उस समय छोटे लग सकते थे लेकिन वे जीवन भर छात्रों के साथ रहे। उन्होंने बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद की, डर के कारण नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति के कारण। आज के बच्चे बहुत अलग माहौल में बड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया उनके दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। जहां यह ज्ञान और जुड़ाव प्रदान करता है, वहीं उन्हें नकारात्मकता, हिंसा, बदमाशी, अवास्तविक जीवनशैली और निरंतर तुलना के संपर्क में भी लाता है। युवा दिमाग अभी विकसित हो रहे हैं और वे जो देखते और सुनते है, उससे आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। उचित मार्गदर्शन के बिना, उनके लिए इन प्रभावों को स्वस्थ तरीके से समझना मुश्किल हो जाता है। यही वह जगह है जहां मोरल साइंस फिर से बदलाव ला सकती है। यह उन्हें साथियों के दबाव को संभालने, असफलता से निपटने और बिना अहंकार के आत्मविश्वास विकसित करने में मदद कर सकती है। यह उन्हें सिखाता है कि सफलता केवल जीतने के बारे में नहीं, बल्कि निष्पक्ष, दयालु और ईमानदार होने के बारे में भी है। सुबह की सभाएं भी दिन की लय तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिन की शुरुआत राष्ट्रगान या वंदे मातरम या किसी देशभक्ति गीत के साथ करने से एकता और अपनेपन की भावना पैदा होती है। यह छात्रों को याद दिलाता है कि वे अपने आप से बड़ी किसी चीज (अपने देश) का हिस्सा हैं। यह जबरदस्ती नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास के माध्यम से सम्मान और गर्व की भावना जगाता है। भजन या एक साधारण भक्ति या प्रेरणादायक गीत जोड़ने से युवा दिमागों में शांति और एकाग्रता आ सकती है। विचार एक शांतिपूर्ण क्षण बनाने का है, जहां बच्चे अपना शैक्षणिक कार्य शुरू करने से पहले रुकें, सांस लें और सकारात्मक विचारों से जुड़ें। ऐसी दुनिया में, जहां बच्चे लगातार स्क्रीन और तेज कंटेंट से उत्तेजित रहते हैं, कुछ मिनटों का शांत चिंतन भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि स्कूलों को केवल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए, जो पारंपरिक या पुरानी लगती हो। लेकिन सच तो यह है कि चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा अधूरी है। एक बच्चा जो उच्च अंक प्राप्त करता है लेकिन जिसमें सहानुभूति या अखंडता की कमी है, वह वास्तविक जीवन में संघर्ष कर सकता है।

दूसरी ओर, एक बच्चा जो मूल्यों को समझता है, भले ही वह पढ़ाई में औसत हो, उसके एक जिम्मेदार और संतुलित वयस्क के रूप में विकसित होने की संभावना अधिक होती है। मोरल साइंस को फिर से शुरू करने का मतलब पीछे जाना नहीं, इसका अर्थ है नींव को मजबूत करना।

आधुनिक समय के अनुरूप इस विषय को अपडेट किया जा सकता है। पाठों में डिजिटल जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और दैनिक जीवन में दयालुता के महत्व जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तकों की बजाय वास्तविक जीवन के उदाहरणों, समूह चर्चाओं और गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह, सुबह की सभाओं को आकर्षक और समावेशी बनाया जा सकता है। गान और भजन के साथ, छात्र मूल्यों के बारे में छोटे विचार, कहानियां या अनुभव साझा कर सकते हैं। वे दयालुता, टीम वर्क या ईमानदारी के उन कार्यों के बारे में बात कर सकते हैं, जो उन्होंने देखे या किए है। यह भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और मूल्यों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाता है, न कि केवल कक्षा का एक विषय। माता-पिता और शिक्षक दोनों की इसमें भूमिका है। अकेले स्कूल एक बच्चे को पूरी तरह से आकार नहीं दे सकते लेकिन वे एक मजबूत वातावरण बना सकते हैं, जहां अच्छे मूल्यों को प्रोत्साहित और उनका अभ्यास किया जाता है। जब बच्चे स्कूल में सिखाई जाने वाली बातों और घर में मिलने वाले अनुभवों के बीच निरंतरता देखते है, तो प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। आज की दुनिया में, जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और विकर्षण बढ़ रहे हैं, बच्चों को केवल शैक्षणिक ज्ञान से अधिक की आवश्यकता है। उन्हें मार्गदर्शन, भावनात्मक शक्ति और सही-गलत की स्पष्ट समझ की आवश्यकता है। मोरल साइंस और सार्थक सुबह की सभाएं सरल लेकिन प्रभावी तरीके से यह सहायता प्रदान कर सकती हैं। पीछे मुड़कर देखने पर, कई वयस्कों को अपने स्कूल के दिन केवल पाठों और परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा सीखे गए मूल्यों, गाए गए गीतों और अनुशासन और एकजुटता की भावना के लिए याद आते हैं। इन यादों ने उन्हें वह बनाया, जो वे आज हैं। अब समय आ गया है कि आज के बच्चों को भी वही अवसर दिया जाए। यह बच्चों को जीवन के लिए तैयार करने के बारे में है, न कि केवल करियर के लिए। यह उन्हें विचारशील, सम्मानजनक और जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में बढ़ने में मदद करने के बारे में है। लंबे समय में, यही वास्तव में एक मजबूत समाज का निर्माण करता है। दि स्कूल यह कदम उठाते हैं, तो इसका प्रभाव मार्कशीट में तुरंत या प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा लेकिन यह बच्चों के सोचने और दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके में दिखाई देगा। और अंत में, यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है।-देवी एम. चेरियन

सम्पादकीय...

उन्नाव की तस्वीर

उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर युवाओं की ऊर्जा और उनकी उद्यमिता को नया आकाश प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान' आज एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह योजना मात्र सरकारी आंकड़ा भर नहीं है बल्कि उन हजारों युवाओं के संकल्प की सिद्धि है जिन्होंने अभावों के बीच भी स्वरोजगार का सपना पाल रखा था। विशेष रूप से जनपद उन्नाव के संदर्भ में बात करें, तो यहाँ की मिट्टी के सपूतों ने इस योजना का लाभ उठाकर न केवल स्वयं को स्वावलंबी बनाया है, बल्कि अन्य लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलकर एक नए आर्थिक युग का सूत्रपात किया है। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान का मूल मंत्र युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण और तकनीकी मार्गदर्शन ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच की उस खाई को पाटने का काम किया है, जहाँ अक्सर पूंजी के अभाव में प्रतिभाएं दम तोड़ देती थीं। उन्नाव में इस अभियान की सफलता की गूँज अब हर गली-मोहल्ले में सुनाई दे रही है, जहाँ के युवा अपनी सफलता की गाथा स्वयं लिख रहे हैं। इसी कड़ी में शिव नगर, उन्नाव के निवासी संतोष कुमार की कहानी अत्यंत प्रेरणादायी है। संतोष ने अपनी उद्यमिता के सपने को गति देने के लिए मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान का सहारा लिया और बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्राप्त कर सोलर पैनल मरम्मत एवं बिक्री का कार्य सुचारू रूप से संचालित करना प्रारंभ किया। आज वे न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण सम्मानजनक ढंग से कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने साथ पाँच अन्य स्थानीय युवाओं को भी रोजगार प्रदान किया है। वे एक ऐसा उदाहरण हैं जिन्होंने सरकार के सहयोग से अपनी उद्यमशीलता को साकार किया है। इसी प्रकार, उन्नाव के ही रहने वाले नितेश वर्मा ने कोचिंग सेंटर के संचालन हेतु पाँच लाख रुपये का ऋण लेकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना शुरू किया है, जिससे वे स्वयं आत्मनिर्भर होकर समाज को शिक्षित करने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। उद्यमिता का यह विस्तार केवल तकनीकी या शैक्षणिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कलात्मक क्षेत्रों में भी इसकी गहरी पैठ दिखती है। उन्नाव निवासी मनी सभावाली ने मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के तहत बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्राप्त कर एक आधुनिक फोटो स्टूडियो और प्रिंटिंग का कार्य शुरू किया। उन्होंने न केवल डिजिटल फोटोग्राफी में अपनी पहचान बनाई, बल्कि चार अन्य लोगों को भी अपनी इकाई में रोजगार से जोड़ा। उद्यमिता की इसी लहर में स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र को भी नया आयाम मिला है। आदर्श नगर, उन्नाव के कुलदीप कुमार ने फिटनेस के प्रति अपनी रुचि को व्यवसाय में बदलते हुए पाँच लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया और एक जिम एवं फिटनेस सेंटर की स्थापना की। आज उनके इस केंद्र से चार अन्य लोग जुड़े हुए हैं, जो रोजगार के साथ-साथ समाज को स्वस्थ रहने का संदेश भी दे रहे हैं। वहीं, शिव नगर के ही अरुण वर्मा ने सीएससी (जन सेवा केंद्र) के संचालन के लिए ऋण लिया, जिससे वे ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

घर बैठे खतौनी की प्रमाणित नकल: डिजिटल इंडिया की दिशा में उत्तर प्रदेश का सशक्त कदम

डिजिटल व्यवस्था के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि सभी नागरिकों के पास इंटरनेट की उपलब्धता या डिजिटल साक्षरता नहीं है। खासकर बुजुर्ग और कम पढ़े-लिखे लोग इस प्रक्रिया को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के प्रयास और कॉमन सर्विस सेंटर जैसे विकल्प इन चुनौतियों को काफी हद तक कम कर रहे हैं। भविष्य में इस सेवा को और अधिक उन्नत बनाने की संभावनाएं भी हैं। जैसे कि मोबाइल ऐप के माध्यम से और सरल इंटरफेस, बहुभाषी समर्थन, और अधिक सुरक्षित डिजिटल सत्यापन प्रणाली। इससे यह सेवा और अधिक व्यापक और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सकती है। समग्र रूप से देखा जाए तो खतौनी की प्रमाणित नकल को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की यह पहल एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह न केवल प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे न केवल लोगों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि शासन व्यवस्था में विश्वास और पारदर्शिता भी और अधिक बढ़ी है।

-आशिया खातून

भारत तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां शासन और प्रशासन की पारंपरिक प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है-खतौनी की प्रमाणित नकल को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराना। यह पहल न केवल आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। पहले जहां किसी व्यक्ति को अपनी जमीन से संबंधित खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए तहसील या कचहरी के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है। लंबी कतारों में लगना, समय की बर्बादी, दलालों का हस्तक्षेप और अनावश्यक खर्च जैसी समस्याएं अब अतीत की बात हो गई हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे, कभी भी, मात्र भूमि का विवरण फीड कर एक क्लिक में खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त कर सकता है। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक राजस्व विभाग के आधिकारिक पोर्टल या पर जाकर लॉगिन करते हैं। इसके बाद 'खतौनी की नकल' विकल्प का चयन कर उन्हें अपने जिले, तहसील और ग्राम की जानकारी भरनी होती है। फिर संबंधित गाटा संख्या का चयन किया जाता है। जैसे ही निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, प्रमाणित प्रति तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सहज और तेज है कि इसे कोई भी सामान्य नागरिक बिना किसी विशेष तकनीकी ज्ञान के भी आसानी से पूरा कर सकता है। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध है। पहले जहां सरकारी दफ्तरों के समय पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब यह सेवा दिन-रात कभी भी उपयोग की जा सकती है। इससे खासकर उन लोगों को काफी सुविधा मिली है जो नौकरी या अन्य कारणों से दिन में समय नहीं निकाल पाते थे। साथ ही, यूपीआई सहित विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों के कारण भुगतान की प्रक्रिया भी बेहद सरल और सुरक्षित हो गई है। डिजिटल खतौनी सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता है। पहले कई बार दस्तावेजों में गड़बड़ी, देरी या भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं। लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण हर चरण रिकॉर्ड में रहता है, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम हो जाती है। इससे आम नागरिकों का विश्वास भी शासन व्यवस्था में और अधिक बढ़ा है। इसके अलावा, यह पहल समय और संसाधनों की बचत भी सुनिश्चित करती है। लोगों को अब अपने काम के लिए छुट्टी लेने, लंबी दूरी तय करने या बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे न केवल उनका समय बचता है, बल्कि यात्रा और अन्य खर्चों में भी कमी आती है। यह पहल पर्यावरण के लिए भी सकारात्मक है क्योंकि इससे कागज के उपयोग में कमी आती है और अनावश्यक यात्रा घटती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सेवा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अक्सर गांवों में रहने वाले लोगों को सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती थी। लेकिन अब इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ वे भी इस सुविधा का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की डिजिटल खाई भी धीरे-धीरे कम हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल 'डिजिटल इंडिया' के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहुंचाना और उन्हें सशक्त बनाना है। खतौनी की ऑनलाइन प्रमाणित नकल इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो दर्शाता है कि कैसे तकनीक का उपयोग कर शासन को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस पहल का एक और सकारात्मक प्रभाव यह है कि इससे सरकारी कर्मचारियों पर कार्यभार भी कम हुआ है। पहले जहां एक-एक आवेदन को मैन्युअल रूप से प्रोसेस करना पड़ता था, वहीं अब अधिकांश काम स्वचालित हो गया है। इससे कर्मचारी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। डिजिटल व्यवस्था के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि सभी नागरिकों के पास इंटरनेट की उपलब्धता या डिजिटल साक्षरता नहीं है। खासकर बुजुर्ग और कम पढ़े-लिखे लोग इस प्रक्रिया को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के प्रयास और कॉमन सर्विस सेंटर जैसे विकल्प इन चुनौतियों को काफी हद तक कम कर रहे हैं। भविष्य में इस सेवा को और अधिक उन्नत बनाने की संभावनाएं भी हैं। जैसे कि मोबाइल ऐप के माध्यम से और सरल इंटरफेस, बहुभाषी समर्थन, और अधिक सुरक्षित डिजिटल सत्यापन प्रणाली। इससे यह सेवा और अधिक व्यापक और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सकती है। समग्र रूप से देखा जाए तो खतौनी की प्रमाणित नकल को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की यह पहल एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह न केवल प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे न केवल लोगों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि शासन व्यवस्था में विश्वास और पारदर्शिता भी और अधिक बढ़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह डिजिटल पहल आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल वर्तमान में लाभकारी है, बल्कि भविष्य में भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

भारत का ऑपरेशन सिंदूर - रणनीतिक विजय का एक वर्ष

आज से एक साल पहले, 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसने सिर्फ नीति की घोषणा से आगे बढ़कर उसे निर्णायक कार्रवाई में बदल दिया। यह भारत की धरती पर दशकों से जारी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने के तरीके में बड़ा बदलाव था। कई मायनों में ऑपरेशन सिंदूर भारत के उस लंबे संघर्ष में एक अहम मिसाल बन गया जिसमें पाकिस्तान द्वारा गैर-राज्य तत्वों को प्रॉक्सी हिंसा के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का जवाब दिया गया। इस अभियान के पीछे भारत का राजनीतिक इरादा पूरी तरह साफ और अडिग था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों के बर्बर हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ प्रतीकात्मक या सीमित नहीं थी। यह पूरी तरह योजनाबद्ध, समयबद्ध और स्पष्ट उद्देश्य वाली कार्रवाई थी। 88 घंटे तक चले इस अभियान ने साफ दिखाया कि भारत ने तय लक्ष्यों के साथ सुनियोजित जवाबी रणनीति अपनाई और अपने उद्देश्य पूरे करने के बाद अपनी शर्तों पर इसे समाप्त किया। राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से इस अभियान की दो बातें खास तौर पर ध्यान देने योग्य हैं। पहली, हमलों का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। लक्ष्य सिर्फ नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे। यह एक सोची-समझी रणनीतिक बढ़त थी, जिसने पाकिस्तान की कथित परमाणु सीमाओं और उसकी प्रतिरोधक नीति को सीधे चुनौती दी। दूसरी, इस अभियान ने दिखाया कि आज के सूचना युग के युद्धों में तकनीक कितनी केंद्रीय भूमिका निभाती है। ब्रह्मोस मिसाइलों, लोइटरिंग हथियारों, नेटवर्क आधारित प्रणालियों और बहु-स्तरीय वायु एवं मिसाइल रक्षा तंत्र के इस्तेमाल ने साफ किया कि अब युद्ध सटीकता, तेजी और बेहतर समन्वित युद्धक्षेत्र समझ पर आधारित है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह भारत की उस नई युद्ध रणनीति का प्रदर्शन भी था, जिसमें दूर से मार करने की क्षमता, तेज निर्णय प्रक्रिया और कई मोर्चों पर एकीकृत कार्रवाई प्रमुख है। 7 मई 2025 को शुरू हुआ यह अभियान पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ढांचे पर तेज, सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई थी। यह भारत की समन्वित सैन्य क्षमता का नियंत्रित लेकिन बेहद प्रभावशाली प्रदर्शन था, जिसका मकसद दुश्मन पर कीमत थोपना था, बिना संघर्ष को बेवजह बढ़ाए। एक साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर भारत की बढ़ती रणनीतिक परिपक्वता का प्रमाण माना जाता है-यानी परमाणु शक्ति से लैस दुश्मन को जवाबदेह ठहराने की क्षमता, वह भी स्पष्ट उद्देश्य, मजबूत इरादे और संतुलित रणनीति के साथ। आज के कई युद्ध जहां लंबे और अनिर्णायक बन जाते हैं, वहीं ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट लक्ष्य और ठोस कार्रवाई के लिए अलग दिखा। इसका राजनीतिक उद्देश्य साफ था-आतंकवाद के ढांचे और उसे समर्थन देने वालों पर सीधी और ठोस चोट करना। लक्ष्य पूरा होते ही अभियान को सीमित रखा गया। टारगेट चुनने में भी संयम और दृढ़ता दोनों दिखे। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, ताकि उनकी क्षमता कमजोर हो, लेकिन आम नागरिकों को नुकसान और अन्य सहायक क्षति न्यूनतम रहे। सैन्य संचालन के स्तर पर यह अभियान भारत की दूर से सटीक हमला करने वाली युद्ध क्षमता के और परिपक्व होने का संकेत था। लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइलों और प्रिसिजन हथियारों से लैस राफेल, साथ ही ब्रह्मोस प्रणाली से जुड़े सुखोई एसयू-30एमकेआई जैसे प्लेटफॉर्म ने बड़े दायरे में गहराई तक समन्वित हमले संभव बनाए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आगे बढ़कर पाकिस्तान के पंजाब के भीतर तक कार्रवाई का विस्तार इस बात का संकेत था कि भारत ने अपनी पुरानी स्व-निर्धारित सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए कथित सुरक्षित ठिकानों को भी चुनौती दी। इस अभियान की रक्षा व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही। एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन या मिसाइलों के जरिए किसी भी जवाबी हमले को प्रभावी ढंग से निष्फल कर दिया। आक्रामक मारक क्षमता और मजबूत रक्षात्मक सुरक्षा के इस मेल ने साफ दिखाया कि आधुनिक युद्ध में नेटवर्क आधारित समन्वय और बहु-स्तरीय सुरक्षा कितनी जरूरी हो चुकी है।

रणनीतिक सिद्धांत के स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर ने एक साथ तीन अहम सीमाएं पार कीं। जिम्मेदार लक्ष्य चयन, संतुलित सैन्य बल का इस्तेमाल और स्पष्ट दबावकारी संदेश। इसने दिखाया कि जब कार्रवाई साफ राजनीतिक इरादे, सटीक सैन्य लक्ष्य और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के साथ की जाए तो दुश्मन को सजा दी जा सकती है बिना हालात को अनियंत्रित युद्ध में बदले। भारत ने युद्ध का दायरा पूरी तरह बढ़ाने के बजाय उसे सीमित लेकिन प्रभावी तरीके से फैलाया, जिससे पूर्ण युद्ध से बचते हुए भी दुश्मन पर ठोस कीमत थोपी गई। इस अभियान की एक और बड़ी खासियत थी-तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और पूरे रक्षा तंत्र का एकीकृत संचालन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की स्थापना के बाद विकसित नई रक्षा संरचना का असर साफ दिखा। समुद्री मोर्चा, वायु शक्ति और जमीनी लक्ष्य-ये अलग-अलग अभियान नहीं थे, बल्कि एक ही संयुक्त रणनीति के हिस्से थे। इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बढ़ती ताकत ने और मजबूत बनाया। स्वदेशी प्लेटफॉर्म, सटीक हथियार प्रणालियां, काउंटर-ड्रोन तकनीक और आईएसआर (इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस) जैसी घरेलू क्षमताओं की बढ़ती भूमिका ने दिखाया कि भारत धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत की औद्योगिक और तकनीकी गहराई का भी प्रमाण था। अब मजबूत रक्षा तैयारी सीधे देश की औद्योगिक क्षमता से जुड़ चुकी है। कूटनीतिक स्तर पर भी यह अभियान बेहद सोच-समझकर चलाया गया। भारत ने अपनी कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जवाब और आत्मरक्षा के दायरे में रखकर पेश किया जिससे ऑपरेशन सिंदूर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नैतिक और रणनीतिक आधार बना। सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक संदेशों के बीच यह तालमेल भारत के लिए रणनीतिक स्पेस बनाए रखने में बेहद अहम साबित हुआ।

आखिरकार, ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियत उसका सही समय पर और स्पष्ट तरीके से समाप्त होना था। अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद भारत ने तय समयसीमा के भीतर अभियान रोक दिया जिससे वह उन लंबे और दिशाहीन संघर्षों से बचा रहा जो आज कई आधुनिक युद्धों की पहचान बन चुके हैं। इसकी शुरुआत, संचालन और समापन, तीनों में दिखाई गई स्पष्टता और सटीकता ही इस अभियान की सबसे बड़ी पहचान रही। एक साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर की असली विरासत सिर्फ दुश्मन को हुए नुकसान में नहीं, बल्कि उस नई मिसाल में है जो इसने कायम की। इसने दिखाया कि संतुलित, तकनीक से लैस और राजनीतिक नेतृत्व से निर्देशित सैन्य कार्रवाई दुश्मन पर भारी कीमत डाल सकती है, उसकी रणनीति बदल सकती है और फिर भी नियंत्रित दायरे में रह सकती है। यह परमाणु खतरे के बीच सीमित युद्ध के लिए भारत के उभरते मॉडल को दिखाता है- इरादों में मजबूत, कार्रवाई में सटीक और संयम में अनुशासित।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीपलवाला रोड, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो.: 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होगे। (DELHIN/2019/08862)

जुआ खेलने के दौरान बनी लूट की साजिश, साथियों ने ही किया वार

गोरखपुर।

कैम्पियरगंज पुलिस ने 3 लुटेरों को दबोचा, नगदी, मोबाइल व बाइक बरामद

थाना कैम्पियरगंज पुलिस को लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 13 हजार रुपये नगद, एक मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना कैम्पियरगंज में पंजीकृत मुकदमा संख्या 211/2026 से संबंधित तीन अभियुक्तों–रविन्द्र निषाद, मुन्ना लाल मौर्य और गिरजेश यादव–को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, 25 अप्रैल 2026 को वादी मेहदावल से पीपीगंज

जा रहा था, तभी रास्ते में तीन अज्ञात बाइक सवारों ने उसे रोककर मारपीट की और 77 हजार रुपये नगद व मोबाइल फोन लूट लिया। मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 13 हजार रुपये, एक मोबाइल और दो मोटरसाइकिल बरामद की।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धाराओं में संशोधन करते हुए धारा 310(2), 3(5) व 317(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र ने पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सभी अभियुक्त आपस में जुआ खेलते थे और आपसी मुखबिरी के आधार पर ही लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस टीम में एसओजी, स्वाट, सर्विलांस और थाना कैम्पियरगंज की संयुक्त टीम शामिल रही, जिनकी सक्रियता से यह सफलता मिली। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बारिश के बीच सड़कों पर उतरे नवागत नगर आयुक्त

गोरखपुर।

शहर का किया निरीक्षण, जलनिकासी व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश

बुधवार शाम हुई बारिश के दौरान नवागत नगर आयुक्त अजय जैन ने अपर नगर आयुक्त के साथ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जलभराव की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जलनिकासी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने गोलघर, धर्मशाला ओवरब्रिज, असुरन, सिनेमा रोड, विजय चौक और सावित्री हॉस्पिटल सहित कई प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां-जहां जलभराव और नालों के जाम होने की समस्या मिली, वहां तत्काल कार्रवाई

के निर्देश दिए गए। सावित्री हॉस्पिटल के सामने कूड़े के कारण चोक हुए नाले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने संबंधित सफाई निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से विधिवत सफाई कराने के निर्देश दिए, ताकि जलनिकासी सुचारु रूप से हो सके और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। नगर आयुक्त अजय जैन ने स्पष्ट कहा कि बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने, नालों की नियमित सफाई और जलनिकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीम को अलर्ट मोड में रहकर कार्य करने और शहरवासियों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा गया। इस दौरान नगर निगम के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोड कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही योगी सरकार

गोरखपुर।योगी सरकार शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी रोड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ कर रही है। गोरखपुर में मुख्य मार्गों को फोरलेन कनेक्टिविटी देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास से दशकों तक पिछड़े रहे दक्षिणांचल को हो रहा है। दक्षिणांचल में उरुवा, धुरियापार, शाहपुर, बेलघाट मार्ग का चौड़ीकरण कार्य जहां अंतिम दौर में है तो वहीं सिकरीगंज, बेलघाट, लोहरिया मार्ग के भी सुदृढ़ीकरण का कार्य दो तिहाई से अधिक पूरा हो चुका है। इन मार्गों के कायाकल्प से लाखों की आबादी को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) प्रांतीय खंड द्वारा करीब 18 किमी की लंबाई में उरुवा, धुरियापार, शाहपुर, बेलघाट मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जा रहा है। 57.68 करोड़ रुपये की लागत वाली इस सड़क परियोजना की भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत है और जून माह के अंत तक शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस मार्ग को दक्षिणांचल की कनेक्टिविटी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड द्वारा ही 8 किमी लंबे सिकरीगंज, बेलघाट, लोहरिया मार्ग का भी 22.32 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है।

पत्रकार हितों को लेकर सक्रिय हुई मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति, डीएम व एसपी को सौंपे मांगपत्र

कुशीनगर।

मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति, कुशीनगर ने पत्रकार हितों एवं प्रशासनिक समन्वय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को मांगपत्र सौंपा। समिति ने जनपद में कार्यरत मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची सभी संबंधित विभागों, थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने की मांग की, ताकि समाचार संकलन कार्य में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। समिति अध्यक्ष एस.एन. शुक्ला के नेतृत्व में दिए गए पत्र में कहा गया कि सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं मीडिया संस्थानों के माध्यम से जनहित से जुड़े समाचारों का संकलन एवं प्रसारण करते हैं। ऐसे में संबंधित विभागों तक उनकी अधिकृत सूची पहुंचना आवश्यक है, जिससे पत्रकारों को कार्य के दौरान अनावश्यक असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त समिति ने नगर पालिका क्षेत्र में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पत्रकारपुरम कालोनी हेतु भूमि आवंटन की मांग भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी।

मांगपत्र में कहा गया कि पत्रकार लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ हैं, जो विपरीत परिस्थितियों एवं सीमित संसाधनों में भी निष्पक्ष रूप से जनसमस्याओं को सामने लाने का कार्य करते हैं। पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना उनके सम्मान एवं सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस दौरान समिति के संरक्षक प्रभु नाथ गुप्त, उपाध्यक्ष अजय मिश्र, आर.के. भट्ट, अशोक शुक्ल, महामंत्री भानु प्रताप तिवारी, मंत्री अनिल पांडे, उपेंद्र तिवारी, संगठन मंत्री हेमंत चौरसिया, संतोष सिंह, अभिषेक शाही, शैलेश उपाध्याय, सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।

रामपुर कारखाना की 24 ग्राम पंचायतों में बनेंगी डिजिटल लाइब्रेरी, ग्रामीण युवाओं को मिलेगी आधुनिक अध्ययन सुविधा

भटनी देवरिया। विधानसभा रामपुर कारखाना क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायत सचिवालयों में जल्द ही आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। इस पहल से गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों, युवाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने बताया कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी सोच के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग 4 लाख रुपये की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इन लाइब्रेरी में कंप्यूटर, इंटरनेट एवं डिजिटल अध्ययन सामग्री जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को गांव में ही गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का माहौल मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यह पहल ग्रामीण शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इससे गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

*विधायक ने मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पढ़ेगा गांव – बढ़ेगा गांव और डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, शिक्षा की नई क्रांति आएगी का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है- रामपुर कारखाना विधायक सुरेन्द्र चौरसिया।

आतंकी गतिविधियों के आरोप में कृष्णा मिश्रा गिरफ्तार, गोरखपुर कनेक्शन की जांच तेज

गोरखपुर। आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कृष्णा मिश्रा को यूपी एटीएस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के कौआबाग इलाके से हिरासत में लिया था। वह यहां किराये पर कमरा लेकर रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद अब एटीएस और स्थानीय खुफिया इकाइयां गोरखपुर में उसके नेटवर्क और गतिविधियों की परतें खोलने में जुट गई हैं। एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आखिर वह शहर में किसके संपर्क में था, किन लोगों से उसकी नियमित मुलाकात होती थी और यहां रहते हुए क्या गतिविधियां संचालित कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक, कृष्णा मिश्रा पिछले कुछ समय से कौआबाग इलाके में रह रहा था। हालांकि एटीएस ने अब तक स्थानीय पुलिस को उसके ठिकाने और गतिविधियों से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है। यही वजह है कि गोरखपुर की लोकल यूनिट अब अलग से उसकी दिनचर्या और संपर्कों का ब्यौरा जुटा रही है। जांच एजेंसियों ने उस मकान के मालिक और आसपास किराए पर रहने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि वह यादा मेलजोल नहीं रखता था और अक्सर चुपचाप आता-जाता था। उसके पास आने-जाने वाले लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।एटीएस और खुफिया एजेंसियां कृष्णा के मोबाइल फोन, काल डिटेल रिकार्ड, इंटरनेट गतिविधियों की गहन जांच कर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि जिन लोगों से उसकी लगातार बातचीत होती थी, उन्हें भी निगरानी में लिया गया है। कुछ संदिग्ध नंबरों और संपर्क सूत्रों को चिन्हित कर उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि कृष्णा ने गोरखपुर में रहते हुए कुछ स्थानीय युवकों से संपर्क बनाया था। यही कारण है कि उसके संपर्क में आए लोगों की प्रोफाइल खंगाली जा रही है। पुलिस और खुफिया इकाइयां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि वह किसी मिशन पर यहां सक्रिय था या केवल ठिकाना बनाकर रह रहा था। सूत्रों का कहना है कि एटीएस की पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

उप परिवहन आयुक्त ने किया एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण, बिना परमिट स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कुशीनगर।

उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र गोरखपुर) द्वारा बुधवार को सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित पाए गए। इस दौरान समीक्षा बैठक कर विशेष रूप से स्कूल वाहनों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जनपद में 203 स्कूली वाहनों के परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी है। इस पर उप परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी स्कूल वाहनों को तत्काल वैध परमिट से आच्छादित कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना परमिट संचालित होने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए उन्हें निरुद्ध किया जाए। समीक्षा में यह भी सामने आया कि जनपद के 168 स्कूल वाहनों का फिटनेस एवं पीयूसी समाप्त हो चुका है, जिनके लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं PISVMP पोर्टल पर जनपद के 1672 वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से 250 वाहनों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा अब तक ऑनबोर्ड नहीं किया गया है। इस पर सभी विद्यालयों को शीघ्र वाहन ऑनबोर्ड कराने के निर्देश दिए गए। एआरटीओ मो. अजीम ने बताया कि ब्लॉकवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर 1316 वाहनों का निरीक्षण कराया गया, जिसमें 681 वाहनों में विभिन्न कमियां पाई गईं। इनमें परमिट, फिटनेस एवं अन्य तकनीकी खामियां शामिल हैं। संबंधित प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को डाक, ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजकर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा सभी कमियों को दूर करने के लिए 15 मई तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। उप परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी अपूर्ण वाहनों का पुनः निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के विभिन्न पटलों का भी निरीक्षण किया गया। सभी कर्मचारी कार्य करते हुए पाए गए तथा कार्यालय में कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इसके अतिरिक्त एआरटीओ मो. अजीम द्वारा एनएच-28 फोरलेन, फाजिलनगर एवं पटेहरवा रोड पर प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए बालू लदे वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान छह वाहनों को कसया थाने में निरुद्ध किया गया। इन पर करीब 2.5 लाख रुपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया, जिसमें से 1.5 लाख रुपये जमा भी कराए गए। अधिकारियों ने बताया कि अवैध परिवहन के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

धार्मिक मामलों पर सवाल उठने लगे तो सैकड़ों याचिकाएं आ जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं या धर्म से जुड़े मामलों पर संवैधानिक अदालत में सवाल उठाने लगेंगे, तो सैकड़ों याचिकाएं अलग-अलग रीति-रिवाजों पर आने लगेंगी, जिससे धर्म और सभ्यता दोनों पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ इस समय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें धर्मस्थलों पर महिलाओं के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाया गया है। इनमें केरल का सबरीमाला मंदिर का मामला भी शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और उसकी सीमाओं पर भी विचार किया जा रहा है, जिनमें दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े मामले भी हैं। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत के साथ न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची शामिल हैं।

दाऊदी बोहरा समुदाय ने दायर की थी जनहित याचिका

दाऊदी बोहरा समुदाय की केंद्रीय संस्था ने 1986 में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें 1962 के उस फैसले को हटाने की मांग की थी, जिसमें बंबई बहिष्कार निवारण अधिनियम 1949 को रद्द कर दिया गया था। इस कानून के तहत किसी भी समुदाय के सदस्य को समाज से बाहर करने को अवैध माना गया था। 1962 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्म के अनुसार, उनके धर्मगुरु किसी सदस्य को धार्मिक कारणों से समुदाय से बाहर कर सकते हैं। इसे उनके धर्म का हिस्सा माना गया था। इसलिए 1949 का कानून उस समय संविधान के अनुच्छेद 26(बी) के तहत दिए गए धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया, जो इस तरह के बहिष्कार को गैरकानूनी बनाता था।

वकील ने क्या दलील दी?

वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन बदलाव चाहने वाले दाऊदी बोहरा समूह की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रथा किसी व्यक्ति के सामाजिक या गैर-धार्मिक आचरण के कारण की जाती है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक संरक्षण नहीं मिल सकता। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई प्रथा धार्मिक पहलू भी रखती है लेकिन वह मूल अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, तो उसे संवैधानिक संरक्षण से बाहर रखा जा सकता है। इस दलील पर जवाब देते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, अगर हर कोई संवैधानिक अदालत के सामने कुछ धार्मिक रीति-रिवाजों या धर्म से जुड़े मामलों पर सवाल उठाना शुरू कर दे, तो फिर उस सभ्यता का क्या होगा, जहां धर्म भारतीय समाज से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है?

हम आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने के इरादे पर मजबूती से कायम - पीएम मोदी

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प को सलाम किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक साल पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय बहादुरी का परिचय देते हुए पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के अटूट संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस अभियान ने भारतीय सेनाओं की पेशेवर क्षमता, तैयारी और आपसी समन्वय को दुनिया के सामने मजबूती से पेश किया। साथ ही यह भी दिखाया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों ने देश की सुरक्षा को और मजबूत किया है। मोदी ने कहा कि एक साल बाद भी भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले पूरे तंत्र को खत्म करने के अपने संकल्प पर पूरी मजबूती से कायम है।

गृह मंत्री ने आतंकियों को दी चेतावनी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान भारत की सैन्य शक्ति का ऐतिहासिक प्रतीक बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर हमेशा दुश्मनों को भारतीय सेना की अचूक मारक क्षमता की याद दिलाता रहेगा। अमित शाह ने कहा कि इतिहास इस दिन को भारतीय सेनाओं की सटीक स्ट्राइक क्षमता, खुफिया एजेंसियों की सूक्ष्म जानकारी और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के संयुक्त प्रदर्शन के रूप में याद रखेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों और उनके ठिकानों को सीमा पार जाकर नष्ट किया गया।

गृह मंत्री ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे कहीं भी छिप जाएं, भारत की नजर और सेना की मारक शक्ति से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि यह दिन दुश्मनों के लिए हमेशा एक कड़ा संदेश बना रहेगा। अमित शाह ने इस मौके पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस और बलिदान को भी सलाम किया।

भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को शुरू हुए आज एक साल हो गए हैं। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी तो पाकिस्तान की इस नापाक साजिश और उसकी हरकतों को भारत ने यूं ही नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 7 मई की तड़के सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मौजूद नौ आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर सटीक एयरस्ट्राइक की। इसमें कई आतंकी मारे गए और आतंकी ढांचों को तबाह कर दिया गया। भारत के इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन की सफलता के बाद स्पष्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया रक्षा सिद्धांत स्थापित किया है- कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले की भारी कीमत आतंकियों के साथ-साथ उनके आकाओं (पाकिस्तान) को भी चुकानी होगी, और भारत परमाणु धमकियों के आगे नहीं झुकेगा।

118 विधायक लाओ, तभी होगी शपथ- अड़े तमिलनाडू के राज्यपाल राजेंद्र

चेन्नई ।

विजय को दूसरी बार राजभवन से वापस भेजा

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। टीवीके प्रमुख विजय आज एक बार फिर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि केवल सबसे बड़ी पार्टी होने भर से सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल अपने रुख पर कायम हैं कि विजय को पहले विधानसभा में बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा दिखाना होगा। राजभवन का मानना है कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में अस्थिर सरकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसलिए 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन साबित करना अनिवार्य होगा।

टीवीके के पास कितनी सीटें?

दरअसल, 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था। हालांकि विजय खुद दो सीटों से चुनाव जीते हैं और नियमों के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। ऐसे में पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी।

कांग्रेस ने दिया टीवीके को समर्थन

सरकार बनाने की कोशिश में टीवीके को उस समय बड़ी राहत मिली जब कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन से अलग होकर विजय को समर्थन देने का फैसला किया।

कांग्रेस के पांच विधायक टीवीके के साथ आए, लेकिन इसके बाद भी आंकड़ा केवल 112 तक पहुंच पाया। यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से अभी भी छह विधायक कम हैं। यही वजह है कि राज्यपाल ने फिलहाल शपथ ग्रहण को लेकर कोई हरी झंडी नहीं दी है।

एनडीए के बिहार मंत्रिमंडल में पुत्र उदय, नीतीश के बेटे निशांत समेत 3 पूर्व सीएम के लाल बने मंत्री

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का गुरुवार को पूर्ण विस्तार हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाया जाना प्रमुख आकर्षण रहा। चौधरी के मंत्रिमंडल में अब तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे शामिल हैं - नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन। तीनों ने गुरुवार को शपथ ली। एनडीए ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। हवाई अड्डे से समारोह स्थल जाते समय, सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े लोगों ने मोदी के वाहन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे। इंजीनियरिंग स्नातक निशांत कुमार, जो लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, ने जेडीयू नेतृत्व के लगातार आग्रह के बाद मंत्री पद की शपथ ली। खबरों के मुताबिक, निशांत कुमार ने शुरू में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, यह कहते हुए कि वे कोई भी औपचारिक पद स्वीकार करने से पहले एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपनी साख साबित करना चाहते हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसके 15 मंत्री हैं, जिन्होंने गुरुवार को शपथ ली। इनमें से अधिकतर वे मंत्री हैं जो पिछले साल नवंबर में एनडीए के विधानसभा चुनावों में शानदार वापसी के बाद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल थे। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ ली। विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सम्राट चौधरी के साथ अप्रैल में शपथ ली थी और उन्हें उपमुख्यमंत्री नामित किया गया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के संजय कुमार सिंह और संजय कुमार पासवान मंत्री पद पर वापस आ गए हैं, और इसी तरह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा) और उपेंद्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) के पुत्र संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश भी मंत्री पद पर वापस आ गए हैं।

सीएम मान और केंद्रीय मंत्री बिट्टू को उड़ा देंगे- जालंधर-फरीदकोट में स्कूलों को भी उड़ाने की धमकी, आया मेल

जालंधर/फरीदकोट (पंजाब) ।

पंजाब के सीएम भगवंत मान शुकराना यात्रा के दौरान आज जालंधर और फरीदकोट में हैं। दोनों जिलों के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में सीएम मान और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को कार बम से उड़ाने की भी बात लिखी गई है। जालंधर में बीएसएफ चौक के पास एक्टिवा ब्लास्ट के बाद अब निजी स्कूलों को मिली धमकियों ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, बीएमसी चौक स्थित एपीजे स्कूल को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत एहतियातन सभी छात्रों की छुट्टी कर उन्हें घर भेज दिया। धमकी की सूचना मिलते ही स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस व प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्कूल परिसर की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। एडीसीपी आकर्षि जैन ने बताया कि शहर के 5-6 स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिली हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं, जबकि साइबर क्राइम टीम धमकी भरे ई-मेल की जांच में जुटी हुई है। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूल में मैसेज दिखाकर कहा गया कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद तुरंत छुट्टी कर दी गई। इस घटना के बाद अभिभावकों में भी डर और चिंता का माहौल है।

फरीदकोट में तीन स्कूल-कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी

फरीदकोट में मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुकराना यात्रा से पहले तीन शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ई-मेल के जरिए सादिक के सरकारी कन्या स्कूल, फरीदकोट के दसमेश पब्लिक स्कूल और दसमेश डेंटल कॉलेज को धमकी दी गई। इसके बाद जिला पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और संबंधित संस्थानों को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर फरीदकोट और कोटकपूरा के अधिकतर स्कूलों में छुट्टी कर दी। डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने जांच शुरू कर दी थी। अब तक किसी भी स्कूल या कॉलेज से कोई संदिग्ध या प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

मैंने ममता बनर्जी को हराया, इसीलिए पीए की हत्या- सुवेंदु

कोलकाता । भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है। सुवेंदु ने कहा- इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसकी जितनी भी निंदा करें वह कम है। हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार हो सकती है। उधर चंद्रनाथ की मां ने कहा कि इस हार का बदला मेरे बेटे की हत्या कर लिया गया। कुछ नेताओं ने पहले धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि रथ को चार गोलियां लगी थीं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक मिल गई है। चंद्रनाथ की हत्या बुधवार देर रात 10.30 बजे की गई थी। वे कोलकाता से मध्यमग्राम अपने घर लौट रहे थे। कोलकाता से करीब 20 दूर डोलतला में एक कार रथ की स्कॉर्पियो के सामने खड़ी हो गई। इसी बीच बाइक पर आए हमलावरों ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। दो गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर-पार हो गईं। एक गोली पेट में लगी। उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी। हत्या के बाद हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। उनके ड्राइवर का इलाज जारी है।

नहर में डूबने से तीन युवकों की मौत

तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हर्षपुर में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नहर में नहाने गए पांच युवकों में से तीन की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के अशोकनगर (चंदेरी) स्थित प्राणपुर निवासी मिथुन (30), धर्मेंद्र (20) और बस्तावन निवासी धीरज (22) अपने परिजनों के साथ बस्तावन में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। धीरज के चाचा के लड़के की शादी थी और गुरुवार को ही बारात उजाव बालाजी जानी थी। बारात रवानगी से पहले ये सभी युवक हर्षपुर स्थित अपनी बहन के घर आए थे। दोपहर करीब एक बजे सभी युवक अपने जीजा जगदीश के साथ पास ही स्थित नहर में नहाने चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नहाते समय एक युवक गहरे पानी में जाने लगा, जिसे बचाने के प्रयास में अन्य साथी भी डूबने लगे। शोर सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने जगदीश (32) और राजकुमार (30) को किसी तरह बाहर निकाल लिया, लेकिन मिथुन, धीरज और धर्मेंद्र की पानी में समा जाने से मृत्यु हो गई।

भारत का पाकिस्तान को दो टूक संदेश: पहले आतंकवाद छोड़ों फिर बहाल होगी 'सिंधु जल संधि'

नई दिल्ली । ऑपरेशन सिंदूर का एक साल पूरा होने पर भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि 'सिंधु जल संधि' Indus Waters Treaty तब तक बहाल नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से बंद नहीं करता।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को राज्य नीति की तरह इस्तेमाल करता रहा है और भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Randhir Jaiswal ने नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमला का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने उस आतंकी हमले की सच्चाई देखी थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का करारा जवाब दिया था और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सिंधु जल संधि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के जवाब में स्थगित रखी गई है। पाकिस्तान को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से आतंकवाद का समर्थन छोड़ना होगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारे का आधार रही है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इसे स्थगित कर दिया था, जिसे दोनों देशों के संबंधों में बड़ा रणनीतिक बदलाव माना गया। रिपोर्ट के मुताबिक, एक साल बाद भी भारत ने अपने बांधों के गेट बंद रखे हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में Baglihar Dam के सभी गेट अब भी बंद हैं। यह बांध चिनाब नदी पर बना है और सिंधु जल संधि से जुड़े प्रमुख परियोजनाओं में गिना जाता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'Operation Sindoor' की पहली वर्षगांठ पर कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के संकल्प का प्रतीक था। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की तारीफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, पेशेवर क्षमता और मजबूत इरादे का प्रदर्शन किया। यह अभियान पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था।

अब मुख्यमंत्री नहीं रहीं ममता बनर्जी, राज्यपाल ने बर्खास्त किया पश्चिम बंगाल कैबिनेट

बंगाल। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया. बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने ये फैसला लिया है. ये पूरा निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है.संविधान के हिसाब से विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और मौजूदा विधानसभा 8 मे 2021 से 7 मे 2026 तक अस्तित्व में रही. चूंकि अब नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लिहाजा पुरानी विधानसभा को भंग कर दिया गया. इस आदेश के बाद अब ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं रही. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार (6 मई 2026) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश है. साथ ही उन्होंने सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने और विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया. ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई चुनाव आयोग से थी, जिसने बीजेपी के लिए काम किया. उन्होंने कहा था, 'मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत हुई है. मैं हारी नहीं हूं, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी. लगभग 100 सीट पर जनादेश को लूट लिया गया और उनकी पार्टी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई. बंगाल में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि अब वह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी. उन्होंने कहा था, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुझे फोन करके एकजुटता व्यक्त की. सोनिया जी और राहुल गांधी ने भी मुझसे बात की है. उन्होंने कहा, 'जब तक मैं कुर्सी पर थी, मैंने बहुत कुछ सहन किया.

अब मैं एक आजाद पंछी हूं, एक आम इंसान हूं. मैं संघर्ष करने वाली हूं. मैं सड़कों पर रहूंगी और सभी अत्याचारों के खिलाफ लड़ूंगी.'

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार का शपथग्रहण समारोह नौ मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. शपथ ग्रहण समारोह के लिए करीब 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के सीएम के शामिल होने की संभावना है.

अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, शॉल पहनाते हुए बोले- आप हारीं नहीं, अछा लड़ीं

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव बंगाल पहुंचे हैं। वहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की। बंगाल में 15 साल पुराने टीएमसी शासन के खात्मे और भाजपा की प्रचंड जीत के बाद यह पहली मुलाकात है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि भाजपा को दीदी हमेशा से खटकती रही हैं। अखिलेश का मानना है कि भले ही इस बार आंकड़े पक्ष में न रहे हों, लेकिन ममता बनर्जी ने एक योद्धा की तरह मुकाबला किया है। ममता बनर्जी खुद अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए गेट तक आईं, जबकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया और कहा, दीदी, आप हारी नहीं हैं। अखिलेश ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, वह वाकई काबिले तारीफ है। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने कहा, भाजपा की आंखों में दीदी खटकती हैं, क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। भाजपा सामंती सोच की है, इनके संगी साथी लोग पुरुषवादी लोग हैं। वह लोग नारी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। मैंने इस चुनाव को बहुत करीब से देखा। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और भाजपा का जो रवैया था, वो हैरान करने वाला है। भाजपा ने बंगाल में जो किया, यूपी में उससे कम किया था। बंगाल में उसका ट्रायल किया गया। उन्होंने कहा, भाजपा जिस तरह से काम करती है, उससे अराजकता फैलती है।